RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 268
दि. 30.01.2026, शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, इन 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर

लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक हो गई है. बैठक में सरकार ने 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगा दी है. शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और शहरी विकास से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. इन प्रस्तावों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और शहरी विकास से जुड़े अहम फैसले शामिल रहे. आइए एक नजर डालते हैं किन 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

कैबिनेट ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों और परिषद से मान्यता प्राप्त अनुदानित और स्ववित्तपोषित स्कूलों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (उहरठ), अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वार्डेन, पूर्णकालिक व अंशकालिक शिक्षक-शिक्षिकाओं और प्रधानमंत्री पोषण योजना की रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इस सुविधा का लाभ इन सभी कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्य भी उठा सकेंगे.

माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को भी कैशलेस इलाज

इसके साथ ही प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों और स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी.

कैबिनेट बैठक में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. यह मामला मेरठ जिले की तहसील मवाना के ग्राम नंगला गोसाई से जुड़ा है।

जहां झील की भूमि पर अवैध रूप

से रह रहे 99 विस्थापित परिवारों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (ठॠढ), नई दिल्ली के आदेशों के क्रम में अन्यत्र पुनर्वासित किया जाएगा.

बहराइच में आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का फैसला

मुख्यमंत्री की पूर्व घोषणा के क्रम में जनपद बहराइच के तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) अंतर्गत राजस्व ग्राम भरथापुर, ग्राम पंचायत आम्बा, परगना धमार्पुर में आपदा प्रभावित परिवारों को विस्थापित कर पुनर्वासित करने के लिए आवश्यक भूमि की व्यवस्था के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके तहत प्रभावित परिवारों को भूमि आवंटन के साथ-साथ वहां आवासीय और अन्य आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. गोरखपुर में सीवरेज परियोजना को हरी झंडी, कैबिनेट ने अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन 2.0 (अटफ्वळ 2.0) के तहत नगर निगम गोरखपुर में सीवरेज योजना जोन-ए-3 से संबंधित परियोजना को भी मंजूरी दी.

बेसिक शिक्षा परिषद के 12 लाख से अधिक शिक्षक व कर्मी निजी अस्पतालों में भी करा सकेंगे कैशलेस इलाज

योजना के तहत शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों के कैशलैस इलाज पर 358.61 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार

(जीएनएस)।

लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े शिक्षकों एवं शिक्षा कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक सहित अन्य कर्मी और उनके आश्रित सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते वर्ष शिक्षक दिवस-2025 के अवसर पर इस योजना की घोषणा की थी, जिस पर अब मंत्रिपरिषद ने औपचारिक मुहर लगा दी है। इस निर्णय से बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले करीब 11.95 लाख से अधिक शिक्षक, शिक्षा कर्मी और उनके आश्रित परिवार लाभान्वित होंगे। यह सुविधा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की तर्ज पर लागू की जाएगी, जिसमें आईपीडी (अंतरोगी) उपचार पूरी तरह कैशलेस होगा। योजना के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वार्डेन, पूर्णकालिक व अंशकालिक शिक्षक, प्रधानमंत्री पोषण योजना से जुड़ी रसोइयां तथा इन सभी के आश्रित परिवार के सदस्य शामिल होंगे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि इस योजना पर सरकार द्वारा प्रति कर्मी लगभग 3000 रुपये वार्षिक प्रीमियम के हिसाब से कुल 358.61 करोड़ रुपये का अनुमानित वार्षिक व्यय किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भगवान द्वारकाधीश के दर्शन किए

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भगवान द्वारकाधीश के दर्शन और पूजा-अर्चना कर राज्य के सर्वांगीण कल्याण की प्रार्थना की

गांधीनगर, 29 जनवरी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के चरणों में शीश नवाकर दर्शन किए और धन्यता महसूस की।

मुख्यमंत्री ने भगवान द्वारकाधीश के श्री चरणों में राज्य के नागरिकों की सुख-शांति और समृद्धि की हृदयपूर्वक प्रार्थना की। उन्होंने भक्तिभाव से शास्त्रोक्त विधिपूर्वक पादुका पूजन भी किया।

मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में उपस्थित दर्शनार्थियों का अभिवान स्वीकार किया और सभी को 'जय द्वारकाधीश' कहा।

जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र, द्वारका मंदिर की प्रतिकृति, फुल और तुलसी से बनी अनुग्रहम अगरबत्ती तथा प्रसाद अर्पित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ पूर्व मंत्री और विधायक श्री मुळुभाई बेरा, जिला कलेक्टर श्री राजेश तन्ना, पुलिस अधीक्षक श्री जयराजसिंह वाळा और अग्रणी श्री मयूरभाई गढ़वी सहित स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे।

सुनेत्रा पवार बन सकती हैं महाराष्ट्र डिप्टी सीएम! अजित पवार की पत्नी को लेकर दिग्गज नेता ने किया बड़ा दावा

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन क्रैश में दर्दनाक मौत 28 जनवरी 2026 को हो गई। गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ एनसीपी प्रमुख को लाखों नम आंखों ने बारामती में अंतिम विदाई दी। अजित पवार की हादसे में दुखद मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता प्रफुल्ल पटेल ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को लेकर बड़ा बयान दिया है।

उनके बयान के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या आने वाले समय में सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री बन सकती हैं। हालांकि, अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पटेल के बयान ने सियासी गलियारों में चर्चा को हवा दे दी है।

सुनेत्रा पवार से मिले NCP के दिग्गज नेता

सूत्रों के अनुसार दिवंगत अजित

पवार के असामयिक निधन के बाद,एनसीपी नेताओं ने इस संभावना को लेकर सुनेत्रा पवार से मुलाकात की जिसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे शामिल थे। यह संकेत भीगौरतलब है कि दिवंगत अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराट्र की महायुति गठबंधन सरकार में प्रमुख घटक दल है। अजित की एनसीपी के अलावा महायुति में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल है।

एनसीपी नेता नरहरि जिरवाल ने अजित पवार के निधन के बाद पार्टी के भविष्य पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि "वाहिनी" (सुनेत्रा पवार) को मंत्रिमंडल में शामिल करने की जनता की प्रबल इच्छा है।

गौरतलब है कि प्लेन क्रैश में दिवंगत हुए डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। महायुति में एनसीपी के अलावा भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल है।

आर्थिक सर्वेक्षण देश के कृषि और ग्रामीण भारत की मजबूती का दस्तावेजः शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आर्थिक सर्वेक्षण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सर्वेक्षण के आंकड़े स्पष्ट रूप से दशार्ते

हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कृषि और ग्रामीण विकास- दोनों मोर्चों पर अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है।

श्री चौहान ने कहा कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में औसत वार्षिक विकास दर स्थिर मूल्यों पर 4.4 प्रतिशत रही है, जो वैश्विक औसत से अधिक है।

अंबेडकर प्रतिमा विवादः शिवाजी चौराहा यात्रा रोके जाने पर तनाव, दामोदर यादव का सरकार पर बड़ा आरोप

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज एक बड़ा सामाजिक-राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में संविधान निमार्ता बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प और मजबूत हुआ।

आजाद समाज पार्टी (भीम आर्मी) के मंडल पदाधिकारी दामोदर यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "हम हर हाल में बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में स्थापित करेंगे। यह हमारा अटल और अटूट संकल्प है। किसी भी दबाव में हम पीछे नहीं हटेंगे।"

यह विवाद मई 2025 से चला आ रहा है, जब ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ परिसर में अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने की मांग पर वकीलों के दो गुटों में टकराव हुआ था। एक पक्ष इसे संविधान के सम्मान से जोड़ता है, जबकि दूसरे पक्ष ने परिसर की 'पवित्रता' और 'परंपरा' का हवाला देकर विरोध किया। तब से यह मुद्दा सड़कों, अदालतों और राजनीति तक पहुंच गया है।

भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता, बाबा साहब के अनुयायी, दलित-बहुजन संगठन के पदाधिकारी और आमजन शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मनुवादी सोच के खिलाफ एकजुटता दिखाना और ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रतिमा स्थापना की मांग को तेज करना था।

कार्यक्रम के दौरान दामोदर यादव ने बताया कि मोहन यादव सरकार द्वारा पहले से तय कार्यक्रम के तहत बाबा

साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शिवाजी चौराहा तक शांतिपूर्ण यात्रा निकालने की योजना थी। हजारों लोग जुटे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने यात्रा को शिवाजी महाराज की प्रतिमा तक पहुंचने से रोक दिया। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और जमकर हंगामा हुआ।

दामोदर यादव ने पुलिस और प्रशासन के साथ तीखी बहस की। उन्होंने कड़ा आरोप लगाते हुए कहा, "यह सिर्फ बाबा साहब का नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अपमान है। सरकार जानबूझकर जनभावनाओं को कुचलने का प्रयास कर रही है। शिवाजी चौराहा तक जाने से रोकना संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है।"

संकल्प और आगे की रणनीति

दामोदर यादव ने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से जारी रहेगा। उन्होंने कहा, "हम किसी भी दबाव में नहीं झुकेंगे। यदि सरकार नहीं मानती, तो हम और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। दीक्षा भूमि नागपुर से लेकर भोपाल तक का यह संकल्प अब अटूट हो चुका है।"

उन्होंने मांग की कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जाए, क्योंकि वे संविधान के निमार्ता हैं और न्यायालय संविधान की रक्षा करते हैं। "अगर अन्य राज्यों में अंबेडकर जी की प्रतिमा न्यायालयों में है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं?" उन्होंने सवाल उठाया।

विवाद की पृष्ठभूमि

मई 2025ः ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रतिमा लगाने की मांग पर वकीलों में टकराव, पुलिस हस्तक्षेप।

अक्टूबर 2025ः वकील अनिल मिश्रा की कथित टिप्पणी पर तनाव, सोशल मीडिया पोस्ट हटाए गए, ग्वालियर में प्रतिबंधात्मक आदेश।

जनवरी 2026ः दामोदर यादव ने कई बार चेतावनी दी, 14 मार्च तक समयसीमा तय की।

वर्तमानः भोपाल कार्यक्रम में यात्रा रोके जाने से नया विवाद, पुलिस-कार्यकताओं में बहस।

सीएम मोहन यादव सरकार ने पहले कहा था कि चीफ जस्टिस द्वारा गठित कमेटी का फैसला अंतिम होगा और सरकार उसका समर्थन करेगी। लेकिन कार्यकताओं का आरोप है कि सरकार देरी कर रही है और जनभावनाओं की अनदेखी कर रही है।

सामाजिक संगठनों का समर्थन

कार्यक्रम में विभिन्न दलित-बहुजन संगठनों, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और अन्य सामाजिक कार्यकताओं ने एकजुटता जताई। कई वक्ताओं ने कहा कि यह सिर्फ प्रतिमा का मुद्दा नहीं, बल्कि संविधान के सम्मान और सामाजिक न्याय का सवाल है।

दामोदर यादव ने अंत में अपील की, "बाबा साहब का संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय देता है। हम उसी संविधान के तहत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग पूरी करवाएंगे।" यह मुद्दा अब प्रदेश की राजनीति में गरमा रहा है। आने वाले दिनों में और बड़े आंदोलन की आशंका है।

4 दिनों तक चली सेरेमनी-3 सेनाओं का राष्ट्रपति को नेशनल सैल्यूट

(जीएनएस)।

विजय चौक की रंग-बिरंगी लाइटिंग, तीनों सेनाओं के बैंड्स की मधुर धुनें और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ढ्रीश्रील्लिश ऊ्रं४स्र्री ट४१४) की मौजूदगी में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य समापन हुआ। शाम को आयोजित बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी ने 4 दिनों तक चले गणतंत्र दिवस आयोजनों का शानदार अंत किया। इस दौरान भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड्स ने मिलकर देशभर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। उनके साथ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए।

बीटिंग द रिट्रीट एक 300 साल पुरानी सैन्य परंपरा है। राजा-महाराजाओं के समय में सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद होने का ऐलान होता था। बिगुल बजते ही सैनिक हथियार नीचे रखकर बैरक लौटते थे। आज यह सेना की 'बैरक वापसी' का प्रतीक है। भारत में यह परंपरा 1950 के दशक से चली आ रही है। ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका समेत कई देशों में भी यह आयोजन होता है।

इस साल की सेरेमनी में क्या खास था?

सीटिंग एनक्लोजर के नामः पहली बार विजय चौक की सीटिंग जगहों को भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए -बांसुरी, डमरू, एकतारा, तबला, वीणा, सितार, शहनाई, संतूर, सरोद, पखावज, नगाड़ा, मृदंगम। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने की पहल थी।

लाइटिंग और सजावटः विजय चौक की सभी प्रमुख इमारतें रंग-बिरंगी लाइटिंग से जगमगाईं।

मास बैंड का कमालः तीनों सेनाओं और उअढऋ के बैंड्स ने मिलकर धुनें बजाई -'भारत की शान', 'वंदे मातरम्', 'ड्रमर्स कॉल'। समापन 'सारे जहां से अच्छा' के साथ हुआ।

सेरेमनी का क्रम क्या था? कौन-कौन सी धुनें बजीं?

शुरूआत में सेना ने राष्ट्रपति को नेशनल सैल्यूट दिया। तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' बजा। तीनों सेनाओं के बैंड ने 'कदम-कदम बढ़ाए जा' से शुरूआत की।

पाइप्स एंड ड्रम्स बैंडः 'अतुल्य भारत', 'वीर सैनिक', 'मिली झुली', 'नृत्य सरिता', 'मरूनी', 'झेलम'।

उअढऋबैंड्सः 'विजय भारत', 'हथरोही', 'जय हो', 'वीर सिपाही'।

वायुसेना बैंडः 'ब्रेव वॉरियर', 'ट्वाइलाइट', 'अलर्ट', 'फ्लाइंग स्टार'।

नौसेना बैंडः 'नमस्ते', 'सागर पवन', 'मातृभूमि', 'तेजस्वी', 'जय भारती'।

सेना बैंडः 'विजयी भारत', 'आरंभ है प्रचंड है', 'ऐ वतन, ऐ वतन', 'आनंद मठ', 'सुगम्य भारत', 'सितारे हिंद'।

अंत में मास बैंड ने 'भारत की शान', 'वंदे मातरम्', 'ड्रमर्स कॉल' बजाया।

समापन बिगुल की धुन 'सारे जहां से अच्छा' के साथ।

गणतंत्र दिवस परेड 2026 के बेस्ट अवॉर्ड्स कौन जीते?

बेस्ट मार्चिंग टुकड़ीः

तीनों सेनाओं में: भारतीय नौसेना

उअढऋ और सहायक बलों में: दिल्ली पुलिस

बेस्ट झांकी (राज्य/केंद्रशासित प्रदेश):

पहलाः महाराष्ट्र -थीमः 'गणेशोत्सवः आत्मनिर्भरता का प्रतीक'

दूसराः जम्मू-कश्मीर -'जम्मू-कश्मीर के हस्तशिल्प और लोक नृत्य'

तीसराः केरल -'वॉटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता'

केंद्रीय मंत्रालयों में बेस्ट झांकीः संस्कृति मंत्रालय -'वंदे मातरमः द सोल क्राई ऑफ ए नेशन'

विशेष पुरस्कारः उढहऊ को 'वंदे मातरमः 150 सालों का स्मरण' और डांस ग्रुप को 'वंदे मातरमः द इटरनल रेजोनेंस ऑफ इंडिया'।

राष्ट्रपति, ढट और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी क्यों महत्वपूर्ण?

राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होती हैं। सेरेमनी में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी से यह आयोजन देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बन जाता है। यह सेना और नागरिकों के बीच एकता का भी संदेश देता है।

बीटिंग रिट्रीट का सबसे भावुक पल कौन सा होता है?

समापन में बिगुल की धुन 'सारे जहां से अच्छा' बजना। यह धुन सुनते ही पूरा विजय चौक भावुक हो उठता है। यह पल देशभक्ति और सेना के प्रति सम्मान का प्रतीक होता है।

यूजीसी 2026 बिल मामला : जानिए कौन सी हैं वो दलीलें जिनसे कोर्ट हुआ सहमत

(जीएनएस)।

उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए वऋ्रइ'' 2026 पर अब शीर्ष अदालत ने ब्रेक लगा दिया है। अदालत ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया, जिनमें 2026 के नियमों को गैर-समावेशी, मनमाना और संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया गया था।

कोर्ट ने इन नियमों के प्रवर्तन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक इस मामले की संवैधानिक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक शिक्षण संस्थानों में 2012 के पुराने दिशा-निर्देश ही लागू रहेंगे।

विस्तार से जानते हैं कि कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से क्या-क्या दलीलें पेश कि गईं, कोर्ट ने क्या कहा...

अधिवक्ता विनीत जिंदल और राहुल दीवान द्वारा दायर याचिकाओं में 2026 के नियमों को "मनमाना" करार दिया गया। कोर्ट में दी गई मुख्य दलीलें इस प्रकार थीं:

सुरक्षा का अधिकार केवल एक वर्ग को क्यों?

याचिकाकताओं ने तर्क दिया कि भेदभाव की परिभाषा को केवल

SC/ST/OBC तक सीमित करना गलत है। सामान्य श्रेणी के छात्र भी जातिगत शत्रुता या दुर्व्यवहार का शिकार हो सकते हैं, जिन्हें इस कानून ने सुरक्षा से वंचित कर दिया है।

अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघनः

दलील दी गई कि यह कानून एक "प्रतिकूल वर्गीकरण" पैदा करता है, जो संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार के विरुद्ध है।

रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन (विपरीत भेदभाव):

याचिकाओं में कहा गया कि यह कानून इस एकतरफा धारणा पर टिका है कि भेदभाव केवल एक ही दिशा में होता है, जबकि सवर्ण छात्रों के साथ होने वाले उत्पीड़न की संभावना को पूरी तरह अनदेखा किया गया है।

सरकार और UGC का क्या था पक्ष?

वहीं, भारत सरकार और यूजीसी ने अदालत में 2026 के नियमों का बचाव करते हुए कहा कि ये विनियम ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों की जमीनी सच्चाइयों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। सरकार ने दलील दी कि यह कदमरोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं द्वारा दायर एक पुरानी जनहित याचिका (ढक्छ) के संदर्भ में उठाया गया था।

उन मामलों ने यह उजागर किया था कि संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव के कारण छात्रों को गंभीर मानसिक और सामाजिक पीड़ा झेलनी पड़ी। सरकार के अनुसार, 2026 के नियम सलाहात्मक नहीं बल्कि बाध्यकारी (enforceable) व्यवस्था लाने के उद्देश्य से तैयार किए गए थे, ताकि संस्थानों को जवाबदेह बनाया जा सके।

रउ की तल्ख टिप्पणी: "हम जानते हैं क्या हो रहा है"

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा, "हम जानते हैं कि क्या हो रहा है।" पीठ ने माना कि सुरक्षा का ऐसा कोई 'पदानुक्रम' (HierÔrchy) नहीं बनाया जा सकता जो छात्र आबादी के किसी भी एक वर्ग को सुरक्षा तंत्र से बाहर कर दे। कोर्ट ने रेगुलेशन 3(c) की संकीर्णता को

गिर के जंगल और समूचे लायन लैंडस्केप सहित अन्य वन क्षेत्रों के वन कर्मियों को मिलेंगे विशेष सुविधाओं से सुसज्जित वाहन

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सासण गिर में वन कर्मियों के लिए 183 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

गांधीनगर, 29 जनवरी : वन संपदा और वन्य जीव सृष्टि के मामले में समृद्ध गुजरात में वन्य प्राणी संरक्षण, संवर्धन, रेस्क्यू और पुनर्वास जैसे विभिन्न कार्यों के लिए फील्ड में कार्यरत वन कर्मियों को निश्चित प्रकार की विशेष सुविधाओं से सुसज्जित वाहन प्रदान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार सुबह सासण गिर में ऐसे 183 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

वन विभाग ने विभिन्न प्रोजेक्ट के अंतर्गत फॉरेस्ट फील्ड स्टाफ की पेट्रोलिंग, प्रोटेक्शन और रेस्क्यू जैसे कार्यों के लिए 174 फील्ड बाइक, 6 बोलेरो कैम्पर और 3 मॉडिफाइड रेस्क्यू वाहन उपलब्ध कराए हैं।

इन वाहनों को हरी झंडी दिखाने से पहले मुख्यमंत्री सवेरे शेर दर्शन के लिए गए। उन्होंने अपने दिन की शुरूआत गिर के जंगल में शीत ऋतु की ठंडक के साथ प्रकृति के खुशनुमा सान्निध्य में की और शेर दर्शन की रोमांचक अनुभूति की।

मुख्यमंत्री द्वारा विशेष सुविधाओं से लैस इन वाहनों को संबंधित वन कर्मियों को आवंटित करने के लिए हरी झंडी दिखाने के अवसर पर वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. विनोद राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. जयपाल सिंह और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर का भी दौरा किया।

ये नए वाहन गिर, बृहद गिर और समूचे लायन लैंडस्केप सहित राज्य के अन्य वन क्षेत्रों के वन कर्मियों के लिए और भी कुशलतापूर्वक कार्य करने के साथ-साथ रेस्क्यू के कार्य में भी उपयोगी सिद्ध होंगे।

स्वर्गीय सहदेव माली की स्मृति में तहरी भोज

प्रेस क्लब में उमड़ा पत्रकारिता और राजनीति का संगम,

लखनऊ। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय सहदेव माली की स्मृति में यू०पी० प्रेस क्लब एवं यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट

यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में प्रेस क्लब परिसर में आयोजित तहरी भोज कार्यक्रम भावपूर्ण और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और पत्रकारिता जगत की जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत कर स्व० सहदेव माली को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह गोप, प्रदेश सचिव दीपक रंजन, राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे, पूर्व राज्यसभा सदस्य अरविंद सिंह, इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स की यूपी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष मुकेश सिंह, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी, प्रदेश महामंत्री मुकेश सिंह चौहान एवं प्रदेश प्रवक्ता सचिन रावत विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी, महामंत्री देवराज सिंह, लखनऊ इकाई के अध्यक्ष शिव शरण सिंह तथा यू०पी० प्रेस क्लब के अध्यक्ष रविंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ पत्रकारों, संवाददाताओं एवं सामाजिक कार्यकताओं ने सहभागिता की।

वक्ताओं ने स्वर्गीय सहदेव माली के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे पत्रकारिता के मूल्यों—सत्य, साहस और निष्पक्षता—के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि स्व० माली ने अपने पूरे जीवन में पत्रकारिता को मिशन के रूप में अपनाया और आमजन की आवाज को मजबूती से मंच प्रदान किया।

अज्ञात बदमाशों ने 35 भेड़ों को किया पार, मुकदमा पंजीकृत

खखरेरू/फतेहपुर थाना क्षेत्र के बरैयपुर गांव के पास बनी पानी टंकी के समीप अज्ञात बदमाशों ने रात्रि के अंधेरे में चरवाहों की 35 भेड़ों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अरविंद निवासी खैरई गडरियन का पुरवा एवं वीरेंद्र निवासी नसीरपुर अपनी भेड़ों को चराने के लिए खंतवा की ओर गए हुए थे। वापसी के दौरान अंधेरा हो जाने के कारण दोनों चरवाहे बरैयपुर गांव के किनारे बनी पानी टंकी के पास भेड़ों को बैठाकर खाना-पीना खाकर वहीं सो गए।

पीड़ितों के अनुसार रात्रि लगभग 1 से 2 बजे के बीच अज्ञात बदमाश एक पिकअप वाहन से मौके पर पहुंचे और 35 भेड़ों को वाहन में लादकर फरार हो गए। चरवाहों ने बताया कि उनके पास कुल 140 भेड़ें थीं, जिनमें से 35 भेड़ों को बदमाश ले गए।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू की। पुलिस द्वारा संभावित रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। इस मामले में अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

इस संबंध में थाना प्रभारी विद्या प्रकाश सिंह ने बताया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है तथा जल्द ही आरोपियों का पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी।

हिण्डाल्को रेनुसागर में त्रैवार्षिक वेतन समझौता सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न

अनपरा (सोनभद्र)। हिण्डाल्को रेनुसागर में प्रबंधन एवं श्रमिक संगठनों के बीच त्रैवार्षिक वेतन समझौता सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक एवं आपसी सहमति के वातावरण में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

हिण्डाल्को रेनुसागर की मान्यता प्राप्त श्रम संगठनों तथा प्रबंधन के मध्य त्रैवार्षिक वेतन समझौता बीते 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो गया। श्रम संगठनों ने श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण एवं अन्य मांगों के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रबन्धन को प्रस्तुत किया था और उभय पक्षों के मध्य विभिन्न तिथियों पर हुई कई चक्रों की वार्ता के पश्चात हिण्डाल्को रेनुसागर के टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के के कॉन्फ्रेंस हॉल में यह समझौता सम्पन्न हुआ।

इस समझौते पर प्रबंधन की ओर से हिण्डाल्को रेनुसागर के यूनिट हेड आर पी सिंह, मानव संसाधन प्रमुख रेनुसागर आशीष कुमार पांडेय, संचालन विभाग के प्रमुख मनीष जैन , वित्त एवं वाणिज्य प्रमुख नवींद्र पाठक,ईआर हेड मृदुल भारद्वाज तथा मान्यता प्राप्त श्रम संगठन पदाधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

उक्त अवसर पर हिण्डाल्को रेणुकूट के क्लस्टर हेड समीर नायक एवं हिण्डाल्को रेणुकूट के क्लस्टर एच.आर. हेड जसबीर सिंह ने संयुक्त रूप से सुव्यवस्थित रूप से निष्पादित समझौते को लेकर श्रमिक संगठनों एवं प्रबंधन पक्ष को बधाई दी। इस अवसर पर हिण्डाल्को रेनुसागर के यूनिट हेड आरपी सिंह ने कहा कि पारदर्शी संवाद, विश्वास और सहयोग से श्रमिक हित में वेतन वृद्धि सहित कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। वही हेड एच आर आशीष पांडेय ने समझौते के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को सरल एवं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हुए विस्तृत जानकारी साझा की, जिसकी यूनियन पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने एकमत से सराहना की।

ट्रैक पार रहीं दो महिला ट्रेन की चपेट में आई, कटकर हुई मौत

–सिर पर लकड़ी रखकर पार कर रहीं थी ट्रैक

(जीएनएस)।

फतेहपुर। रेलवे लाइन पार करते समय दो महिलाओं की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों जंगल से लकड़ी काटकर सिर पर रखे रेलवे ट्रैक पार कर रही थीं। उसी समय अचानक तेज रफ्तार ट्रेन के आ जाने पर चपेट में आ गईं।

एकारी गांव निवासी रामभवन रैदास की पत्नी शोभा देवी(40) और मोहल्ले की ही स्वर्गीय अर्जुन पासवान की पत्नी श्यामकली(45) गुरुवार शाम लकड़ी काटने जंगल गईं थीं। एक बार लकड़ी लेकर घर पर रख आईं, पुनः लकड़ी लेकर वह लोग ट्रैक पार रहीं थीं अचानक कानपुर की तरफ से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं, इससे कटकर दोनों की मौत हो गई। मृतका श्यामकली के पति स्वर्गीय अर्जुन पासवान रेलवे कर्मचारी थे, उनकी मौत भी ट्रेन हादसे से हुई थी।

गोविंदनगर पुलिस ने फरार आरोपी पकड़ा : अवैध हथियार बरामद

मथुरा (जीएनएस)। थाना गोविन्दनगर क्षेत्र स्थित आजमपुर मोड़ के पास से पुलिस ने वांछित चल रहे आरोपी को अवैध हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी गोविंदनगर रवि त्यागी और चौकी प्रभारी मसानी महेन्द्र सिंह पुलिस टीम के साथ वांछित अपराधियों की तलाश में जुटे हुए थे।

उसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि आदमपुर मोड़ के पास वांछित चल रहा एक आरोपी खड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रवि त्यागी और चौकी प्रभारी महेन्द्र सिंह पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे वांछित आरोपी साहिल शाह पुत्र सैय्यद साबिर निवासी मदीना मस्जिद के पास, नवनीत नगर थाना कोतवाली, मथुरा को घेरकर पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज दिया है।

शराबबंदी के लिए राष्ट्रीय मोर्चा की हुंकार--मुर्तजा अली

लखनऊ में राष्ट्रीय शराबबंदी संयुक्त मोर्चा और शराबबंदी संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में भारत के विभिन्न प्रदेशों से कार्यकताओं का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। आर्य प्रतिनिधि सभा में आयोजित इस सम्मेलन में आर्य समाज के प्रधान देवेंद्र कुमार वर्मा जी ने अध्यक्षता की और सुलतान सिंह संयोजक रहे।

इस सम्मेलन में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने की तैयारी की गई है, जिसमें मुख्य पार्टियों से शराबबंदी को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की जाएगी। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है, जिसमें शराबबंदी की मांग की जाएगी य।

सम्मेलन में शराबबंदी के मुद्दे पर चर्चा की गई और इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए रणनीति बनाई गई है। शराबबंदी संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुर्तजा अली ने बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य शराबबंदी के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना और इसे मुख्य पार्टियों के घोषणा पत्र में शामिल करवाना है।

इस सम्मेलन में मुख्या तौर पर विभिनं प्रदेशों से आये जिनमे मुर्तजा अली राष्ट्रीय अध्यक्ष शराब बंदी संघर्ष समिति, श्री पी, सी, कुरील भागीदारी आंदोलन , श्री राज कुमार सिंह, (नेशनल युथ पार्टी, इशरत बेग, साद बेग, हलीमा अजीम, फैजुद्दीन सिद्दीकी,फहद हसन, इमरान शेख, मो. कैफ , वाणी दस उड़ीसा से, कल्याणी जी पश्चिम बंगाल से, सुभेन्द्रू जी उड़ीसा से, जीवन चंद्र उत्प्रेती उत्तराखंड से, हरी ॐ गौतम मध्य प्रदेश से, वर्षा विद्या विलास महाराष्ट्र से सम्मिलित हुईं'

गुलरिया चीनी मिल ने महिला थाने को गिफ्ट किया वाटर कूलर

बिजुआ।बलरामपुर फाउंडेशन के तहत गुलरिया चीनी मिल ने सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योजना के तहत शहर के महिला थाने को एक आरओ प्रणाली युक्त वाटर कूलर प्रदान किया है। इसका उद्देश्य थाने में आये फरियादियों के साथ पुलिसकर्मियो को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है।

गुलरिया चीनी मिल के यूनिट हेड योगेश कुमार सिंह की पत्नी बबिता सिंह ने इसका उद्घाटन फीता काटकर किया। यह वाटर कूलर 150 लीटर क्षमता का है।

महिला थाने की एसओ ने मुख्य अथिति को अंगवस्त्र व बुके देकर स्वागत किया।

इस दौरान चीनी मिल के अभिनेष मिश्रा,महिला थाने का स्टाफ मौजूद था।

यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियों का स्वागत

: न्यायालय की टिप्पणियां लोकतांत्रिक, समावेशी एवं एकताबद्ध समाज की दिशा में अहमः सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ईक्विटी रेगुलेशन वापस लेने की मांग

लखनऊ। सामाजिक समरसता मंच, ने UGC इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों एवं निदेर्शों का स्वागत करते हुए कहा है कि ये टिप्पणियां न केवल शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता और समावेशिता की रक्षा करती हैं, बल्कि भारतीय समाज की एकता और सामाजिक सौहार्द को भी मजबूती प्रदान करती हैं।

मंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां यह स्पष्ट करती हैं कि सामाजिक न्याय के नाम पर ऐसे प्रावधान नहीं होने चाहिए जो समाज में नए विभाजन पैदा करें। मंच ने मांग की कि केंद्र सरकार और वऋ्रइ न्यायालय की टिप्पणियों को गंभीरता से लेते हुए नियमो को तत्काल वापस ले ।

मंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह स्पष्ट किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वऋ्रइ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को लागू न किया जाए। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया इन नियमों को ॄअस्पष्टॄ बताते हुए इनके दुरुपयोग की आशंका जताई है, जो इस बात का प्रमाण है कि नियमों को बिना व्यापक विमर्श के लागू करना उचित नहीं है।

मंच ने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का भी स्वागत किया कि

इन नियमों की पुनर्समीक्षा एक छोटी समिति द्वारा की जाए, जिसमें प्रतिष्ठित विधिवेत्ता शामिल हों, ताकि नियम संविधान की भावना, सामाजिक न्याय और व्यावहारिक वास्तविकताओं के अनुरूप हों ।

मंच के अनुसार न्यायालय द्वारा उठाए गए निम्नलिखित प्रश्न अत्यंत गंभीर एवं दूरगामी महत्व के हैं—

क्या ऐसे मामलों में भी भेदभाव माना जाएगा, जहाँ जातिगत पहचान स्पष्ट न हो, जैसे भौगोलिक या क्षेत्रीय आधार पर अपमान?

नियमों में यह मानकर क्यों चला गया है कि उत्पीड़न केवल जाति-आधारित ही होता है, जबकि व्यवहार में अन्य आधारों पर भी भेदभाव और उत्पीड़न होता है?

क्या इस प्रकार के नियमों से हम जातिविहीन समाज की दिशा में अब तक की गई प्रगति से पीछे नहीं जा रहे हैं?

मंच ने सुप्रीम कोर्ट की उस सशक्त टिप्पणी को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया, जिसमें अलग-अलग जातियों के लिए अलग हॉस्टल की अवधारणा पर न्यायालय ने कहा—

ॄभगवान के लिए, ऐसा मत कीजिएङ्क हम सब साथ रहते थे ॄ

मंच ने कहा कि यह टिप्पणी भारत की साझा संस्कृति, भाईचारे और सामाजिक समरसता की आत्मा को दर्शाती है।

मंच ने इस बात से भी सहमति जताई कि शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता झलकनी चाहिए, न कि ऐसे प्रावधान हों जो समाज को और अधिक खांचों में बांटें।

न्यायालय द्वारा यह प्रश्न उठाया जाना भी महत्वपूर्ण है कि जब रेगुलेशन 3(ी) पहले से ही भेदभाव को कवर करता है, तो रेगुलेशन 3(॰) की आवश्यकता क्यों है—क्या यह अनावश्यक नहीं है? साथ ही यह भी कि यदि 2012 के नियम अधिक समावेशी थे, तो 2026 में उनसे पीछे क्यों जाया जा रहा है और रैगिंग जैसे गंभीर मुद्दे को नियमों में क्यों नहीं शामिल किया गया।

सामाजिक समरसता बनाए रखने हेतु यह मंच समाज में व्यापक जनसंपर्क और बैठकों का अभियान जारी रखेगा।

सामाजिक समरसता मंच की आज आशियाना मे हुई बैठक में मुख्यतया रीना त्रिपाठी, सीमा द्विवेदी, रेनू त्रिपाठी, देवेन्द्र शुक्ल, अजय तिवारी, सुरेश चन्द्र बाजपेई, दुर्गेश पांडे, प्रेम तिवारी, सुधांशु मिश्र, शिव दीक्षित, संजय कुमार द्विवेदी , अनिल सिंह उपस्थित थे।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

विमान दुर्घटनाओं के बाद सही निर्णयों की कमी

जिम्मेदारी तय करना जरूरी महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार एक विमान दुर्घटना के शिकार हो गए। इसके पहले विजय रूपाणी भी विमान दुर्घटना के शिकार हुए थे। दो दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है किन्तु लोग माधवराव सिधिया के विमान दुर्घटना को भूल नहीं पाए हैं। जनरल विपिन रावत के हेलीकाप्टर दुर्घटना से भारत की दुनियाभर में जगहंसाई हो चुकी है। इसलिए विमान दुर्घटनाओं के बाद जैसी जांच और सुधार की जरूरत है वह नहीं हो पाती। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का वह स्वायत्त शासी संस्था जिस पर विमानों के परिचालन का दायित्व है, उसकी कार्य पद्धति में सुधार निराशाजनक ही रह जाती है। यही कारण है कि इस विमान दुर्घटना में भी तरह-तरह की बातें की जा रही हैं। यदि सरकार विमान दुर्घटनाओं के बाद रिपोर्ट जारी करती और सुझाए गए तरीकों को अपनाती तो विमान दुर्घटनाएं भी कम होती और साथ ही सरकार एवं संस्थाओं के प्राति आशंका की संभावनाएं भी न रहतीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्थापित परम्पराओं के प्राति उदासीनता भी इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। यह एक नियम है कि कोई विमान उड़ान भरने के पहले इंजीनियर की जांच प्राव्रिया से गुजरता है और जब इंजीनियर विमान के पूरी तरह उड़ने के योग्य होने की पुष्टि करता है तभी पायलट उस विमान को उड़ाते हैं। लेकिन देखा जाता है कि विमान वंपनियां जांच प्राव्रिया से बचती हैं और कभी-कभी तो समयाभाव में राजनेता भी जल्दबाजी के कारण इंजीनियर द्वारा जांच कराने की देरी से बचना चाहते हैं। वुल मिलाकर स्थिति यह है कि अजित पवार जिला परिषद चुनाव प्राचार के लिए जा रहे थे और बारामती हवाई अड्डे के पास यह हादसा हो गया। ऐसी विमान दुर्घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, इसलिए इस विमान दुर्घटना पर भी वुछ लोगों को सवाल उठाने का अवसर मिला किन्तु यह अवसर भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अफसरशाही और डीजीसीए के नकारापन के कारण ही उन्हें मिला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अजित परार के जाने के बाद अब उनके परिवार, पाटा और सरकार का क्या होगा? इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति जानना चाहता है। 6 फरवरी 2024 को ही चुनाव आयोग ने अजित पवार के पक्ष में अपना अंतिम पैसला सुना दिया था। किन्तु स्थानीय चुनावों में जिस तरह अजित पवार और शरद पवार के नेतृत्व वाली दोनों एनसीपी ने चुनाव लड़ा, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि दोनों परिवारों में पाटा के भविष्य को लेकर एक सहमति बनती जरूर दिख रही थी। आज भले ही अजित पवार की पत्नी राज्यसभा की सदस्य हैं किन्तु पाटा चलाने में वह उतनी सक्षम नहीं हैं जितना कि खुद शरद पवार या उनकी पुत्री सुप्रिया सुले हैं। समस्या सबसे बड़ी यह है कि एनसीपी जिसका नेतृत्व अजित पवार कर रहे थे उसके पास 40 विधायक, दो वैबिनेट मंत्री एक लोकसभा सांसद और दो राज्य सभा सदस्य हैं। उनकी पाटा की महत्वाकांक्षा शासन से दूर नहीं हो सकती। इसलिए लगता नहीं कि अजित पवार की एनसीपी राज्य की एनडीए सरकार से अलग होगी। चूंकि शरद पवार और सुप्रिया सुले दोनों ही एनडीए के प्राति पहले जैसे कटु विरोधी रवैया नहीं अपना रहे हैं, इसलिए लगता नहीं कि अजित पवार के जाने के बाद उनकी पाटा देवेन्द्र फडणवीस सरकार से अलग हो जाएगी। लेकिन यह भी सही है कि मुस्लिम आधार होने के कारण एनसीपी भाजपा से अलग अस्तित्व बनाकर रखना भी चाहेगी। बहरहाल राजनीति, पारिवारिक भावना और मौजूदा परिस्थिति के परिप्रोक्ष्य में अजित पवार के जाने के बाद उस एनसीपी का क्या होगा जिसका वह नेतृत्व कर रहे थे, इसका पैसला तो राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व परिवार कर ही लेगा किन्तु विमान हादसों, सरकार एवं डीजीसीए की कार्यवुशलता पर जो बड़ा सवाल उठ रहा है, उसका जवाब पूरे देश को चाहिए।

गुजरात की झाँकी ने लगातार चौथे वर्ष 'पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड' श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर रचा इतिहास

लगातार तीन वर्ष 2023, 2024 और 2025 में भी गुजरात की झाँकी ने इसी श्रेणी में हासिल किया था प्रथम पुरस्कार

गांधीनगर, 29 जनवरीः 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्यपथ पर आयोजित राष्ट्रीय परेड में गुजरात के 'स्वतंत्रता का मंत्रः वंदेमातरम्' थीम आधारित झाँकी ने दर्शकों के बीच विशेष आकर्षण और उत्सुकता पैदा की। गुजरात की इस झाँकी ने गणतंत्र दिवस परेड में 'पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड' श्रेणी में लगातार चौथे वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल ने सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किए गए गुजरात की झाँकी की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्र भक्ति के साथ राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को प्रभावी रूप से उजागर करने के कारण गुजरात की झाँकी को जनता का व्यापक समर्थन और सराहना मिली है।

केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा MyGov पोर्टल पर 26 जनवरी से 27 जनवरी रात 11:45 बजे तक आयोजित ऑनलाइन मतदान में गुजरात की झाँकी पहले घंटे से लेकर दूसरे दिन के अंत तक लगातार अग्रणी रहा और कुल मतों के 43 प्रतिशत वोट प्राप्त कर पीपुल्स चॉइस कैटेगरी में प्रथम स्थान पर विजयी रहा। दूसरे स्थान पर रहे उत्तर प्रदेश को 9 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए, जबकि शेष 15 राज्यों को क्रमशः कम प्रतिशत में मत मिले।

इस वर्ष कर्तव्यपथ पर आयोजित राष्ट्रीय परेड में गुजरात राज्य के सूचना विभाग द्वारा प्रस्तुत झाँकी में 'वंदे मातरम्' और स्वदेशी आंदोलन के समन्वय से उत्पन्न स्वतंत्रता की क्रांति से लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भरता हेतु स्वदेशी मंत्र की यात्रा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया।

उल्लेखनीय है कि पॉपुलर चॉइस कैटेगरी अवॉर्ड में गुजरात की झाँकी की अग्रणी परंपरा की शुरूआत वर्ष 2023 के 74वें गणतंत्र दिवस की

राष्ट्रीय परेड से हुई थी। उस वर्ष राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 'क्लीन ग्रीन एनर्जी युक्त गुजरात' की झाँकी में प्रधानमंत्री के नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के आह्वान को साकार करने में गुजरात की पहल को दशार्या गया था।

इसके बाद वर्ष 2024 के 75वें गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में गुजरात द्वारा प्रस्तुत 'धोरडो झ वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज (वठहळड)' थीम आधारित झाँकी को भी 'पॉपुलर चॉइस' कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, झाँकी की श्रेष्ठता के लिए चयन समिति यानी ज्यूरी चॉइस में भी गुजरात की झाँकी ने वर्ष 2024 में द्वितीय स्थान हासिल किया था।

वहीं वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में गुजरात द्वारा आधुनिक विकास की जिस तेज रफ्तार यात्रा को दशार्या गया, उसे प्राचीन विरासत के साथ जोड़ते हुए प्रस्तुत 'आनर्तपुर से एकतानगर तक- विरासत से विकास का अद्भुत संगम' झाँकी को भी 'पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड' प्राप्त हुआ।

इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2026 में 'स्वतंत्रता का मंत्रः वंदेमातरम्' थीम आधारित गुजरात की झाँकी को भी 'पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड' मिलने से राज्य की उपलब्धियों में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जुड़ गया है।

उल्लेखनीय है कि आगामी 30 जनवरी को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में आयोजित गणतंत्र दिवस के समापन समारोह में केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री की उपस्थिति में गुजरात को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

स्मार्ट सिटी सूरत का स्मार्ट मॉडल : 'डायमंड सिटी' अब बनेगी 'जीरो वेस्ट सिटी'

कूड़ा प्रबंधन में देश की 'रोल मॉडल' डायमंड सिटी अब 'सर्कुलर इकोनॉमी' की ओर अग्रसर

निर्माण कार्य के कूड़े की 100 प्रतिशत रीसाइक्लिंग : हर वर्ष लगभग 500 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटाती है, जो 2,50,000 किलो कोयले की बचत समान है

सूरत महानगर पालिका ने सर्वप्रथम क्लीन कन्स्ट्रक्शन गाइडलाइन लागू की

टिकाऊ शहरी विकास तथा कन्स्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन (सी एण्ड डी) वेस्ट का स्मार्ट मैनेजमेंट कर रही सूरत महानगर पालिका

क्लीन सिटी सूरत में डिमोलिशन वेस्ट अब संपदा बन रहा है

गांधीनगर, 29 जनवरी : एक समय केवल हीरा एवं कपड़ा उद्योग के लिए विख्यात सूरत शहर आज पर्यावरण संरक्षण तथा कूड़ा निकासी के लिए समग्र देश में पथदर्शक बन रहा है। सूरत अब केवल 'डायमंड सिटी' के रूप में नहीं, बल्कि 'जीरो वेस्ट सिटी' की ओर आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए 'अर्बन डेवलपमेंट इयर झ शहरी विकास वर्ष' के अवसर पर सूरत महानगर पालिका ने आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ 'ग्रीन ग्रोथ' को भी प्राथमिकता दी है।

विकास की बड़ी छलांग लगा रहा सूरत शहर अब पर्यावरण संरक्षण में भी देश का नेतृत्व कर रहा है। महानगर पालिका ने आगामी दो वर्ष में शहर में निकलने वाले ठोस निर्माण कार्य कूड़े (सी एण्ड डी वेस्ट) की 100 प्रतिशत रीसाइक्लिंग का लक्ष्य रखा है। ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि शहर का कोई भी कन्स्ट्रक्शन वेस्ट डंपिंग साइट तक पहुँचने की बजाय निर्माण स्थल पर ही या प्लांट में ही रिसाइकल होकर पुनरुपयोग में लिया जाए।

सूरत महानगर पालिका द्वारा शहर के कन्स्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट का वैज्ञानिक ढंग से एकत्रीकरण कर उसे पुनः उपयोग में लेने के लिए कार्यरत सी एण्ड डी वेस्ट रीसाइक्लिंग प्लांट अब समग्र भारत के लिए एक उदाहरणीय मॉडल बना है। यह प्रोजेक्ट शहर की साफ-सफाई के साथ पर्यावरण की रक्षा करने तथा प्राकृतिक संसाधन बचाने में भी योगदान दे रहा है।

निर्माण कार्य के कूड़े की 100

प्रतिशत रीसाइक्लिंग करने वाले सूरत की यह स्मार्ट पहल केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण जतन का बड़ा अभियान बनी है। इस रीसाइक्लिंग प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हर वर्ष 500 प्रतिशत से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटता है, जो 2,50,000 किलो कोयले की बचत समान है। इससे पत्थर तथा रेत जैसे प्राकृतिक संसाधनों के खनन पर बोझ कम हुआ है।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में समग्र भारत में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सूरत ने देश में फिर एक बार स्वच्छता में विशिष्ट पहचान स्थापित की है। सुपर स्वच्छ लीग में सूरत निरंतर अग्रसर रहा है तथा जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की ओर दृढ़ प्रयास हो रहे हैं। सूरत मनपा, राज्य एवं केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन में कूड़े की वैज्ञानिक ढंग से रीसाइक्लिंग तथा वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। शहर में कन्स्ट्रक्शन तथा डिमोलिशन वेस्ट के ठोस कूड़े से बेस्ट प्रोडक्ट्स का उत्पादन करने के लिए सी एण्ड डी प्लांट की स्थापना की गई है।

सूरत के कोसाड में 300 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाला प्लांट जन-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल अंतर्गत कार्यरत है, जिसमें दैनिक अनुमानित 80 मैट्रिक टन डिमोलिशन वेस्ट रीसाइकिल होता है। इस प्रकार; सी एण्ड डी वेस्ट से पेवर ब्लॉक्स तथा विभिन्न प्रकार के कन्स्ट्रक्शन वेस्ट मटीरियल्स से उच्च गुणवत्ता के उत्पाद बनाए जाते हैं।

क्लीन सिटी सूरत में डिमोलिशन वेस्ट अब वेस्ट नहीं, बल्कि वेल्थ बन रहा है। सूरत मनपा द्वारा क्लीन कन्स्ट्रक्शन गाइडलाइन लागू की गई है। ई-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिक घर बैठे ही कन्स्ट्रक्शन वेस्ट उठवाने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। सूरत मनपा द्वारा एक प्रेरणादायी निर्णय लिए जाने से प्लांट में निकलने वाली रिसाइकिल सामग्री को सरकारी टेंडरों में भी 20 प्रतिशत तक रिसाइकिल सामग्री का उपयोग अनिवार्य किया गया है। इस नीति से रिसाइकिल हुई वस्तुओं के बाजार को गति मिलेगी और 'सर्कुलर इकोनॉमी' मजबूत बनेगी।

सूरत मनपा द्वारा लागू क्लीन कन्स्ट्रक्शन गाइडलाइन शहर के वायु प्रदूषण को घटाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। स्मार्ट मॉनिटरिंग के कारण नागरिकों की शिकायतों में कमी आई है और सी एण्ड डी की 100 प्रतिशत रीसाइक्लिंग की जाती है। कन्स्ट्रक्शन साइट्स पर पतरे, शेड्स, धूल नियंत्रण के लिए स्प्रिंकलर्स तथा ग्रीन नेट का अनिवार्य उपयोग; ये सब मिलकर सूरत को अधिक स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुवासित बनाते हैं।

कोसाड स्थित प्लांट में ईंट, कंक्रीट, लोहे के टुकड़े एकत्र कर साइंटिफिक प्रोसेसिंग के जरिये पुनः उपयोग

कोसाड स्थित प्लांट वर्ष 2018 से कार्यरत हुआ। तब से सूरत मनपा द्वारा कलेक्शन सिस्टम मजबूत बनाए जाने से सी एण्ड डी ठोस कूड़े का कलेक्शन क्रमशः बढ़ा है, जिसमें वर्ष 2018-19 में 65,746 मैट्रिक टन, 2019-20 में 37,457 मैट्रिक टन, 2020-21 में 10,614 मैट्रिक टन, 2021-22 में 23,315 मैट्रिक टन, 2022-23 में 41,451 मैट्रिक टन, 2023-24 में 49,381 मैट्रिक टन तथा 2024-25 में 58,106 मैट्रिक टन कन्स्ट्रक्शन-डिमोलिशन वेस्ट का कलेक्शन हुआ है। यह वेस्ट डंपिंग साइट पर जाने की बजाय इसकी रीसाइक्लिंग की गई है।

इस प्लांट में ईंट, कंक्रीट, लोहे के टुकड़े एकत्र कर साइंटिफिक प्रोसेसिंग से उन्हें पुनः उपयोगी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में क्रश्ड एग्रीगेट्स, रिसाइकल्ड रेती, पेवर ब्लॉक तथा कंक्रीट, ईंटों जैसी गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार की जाती है।

करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार व्हील ऑफ फॉर्च्यून पर वापस लेकर आए 90 के दशक का जादू

मुंबईः व्हील ऑफ फॉर्च्यून दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है, और जब बॉलीवुड दिवा करिश्मा कपूर, अनु मलिक और मौनी रॉय के साथ शो में आईं, तो उत्साह का स्तर कई गुना बढ़ गया। अक्षय कुमार द्वारा होस्ट किया गया यह एपिसोड सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर पुरानी यादों, हंसी और पूरे मनोरंजन से भरी एक यादगार यात्रा बन गया। पुरानी यादें तब और गहरी हो गई, जब अक्षय ने एक दिल छू लेने वाला पल शेयर करते हुए कहा, "जैसा कि आप सभी जानते हैं, वह मेरी पहली हीरोइन हैं। मैंने उनके साथ अपनी पहली फिल्म, अपना पहला गाना किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कितनी खूबसूरत हैं।" करिश्मा ने गर्मजोशी से जवाब दिया, "धन्यवाद।" जश्न यहीं नहीं रुकता। यह आइकॉनिक जोड़ी फिल्म दीदार के 34 साल पूरे होने पर अपने यादगार गाने 'दीदार हो गया मुझको प्यार हो गया' को फिर से स्टेज पर पेश करके जादू बिखेरती है और फैंस को

रोमांचित कर देती है। एक और प्रोमो में उनकी चंचल दोस्ती को दिखाया गया है, जिसमें अक्षय मजाक में कहते हैं, "बांद्रा में हर बिल्डिंग के अंदर इनके एक-एक फ्लैट हैं," जिस पर करिश्मा तुरंत जवाब देती हैं, "कुछ भी!" इस मजाक में शामिल होते हुए अनु मलिक कहते हैं, "अक्षय कभी झूठ नहीं बोलते," जबकि करिश्मा चिढ़ाते हुए पलटवार करती हैं, "तुम्हें पता है, वह पूरे जुहू के मालिक हैं!" अक्षय बात को और आगे बढ़ाते हुए लिस्ट में सांताक्रूज और खार को भी जोड़ देते हैं, जिससे लगातार हंसी का माहौल बना रहता है। पुरानी यादों, हास्य और अपनी आइकॉनिक दोस्ती के साथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का यह एपिसोड दर्शकों के लिए एक पूरा एंटरटेनर होने का वादा करता है। अक्षय कुमार द्वारा होस्ट किया जाने वाला व्हील ऑफ फॉर्च्यून 27 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 9:00 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर प्रसारित होगा

'भारत में इस समय किसी भी...', यूजीसी के नए नियमों पर रउ के फैसले के बाद कुमार विश्वास ने मोदी सरकार को किया अगाह

(जीएनएस)।

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यूजीसी के नए नियमों को लेकर चल रहा देश-व्यापी सियासी और अकादमिक घमासान फिलहाल थम सा गया है। अदालत ने 17 दिन पहले लागू किए गए इन नियमों पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अंतरिम अवधि में वर्ष 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। हालांकि, सवाल अब भी कायम है कि यह राहत अस्थायी है या आने वाले समय में यह मामला और अधिक तीखे मोड़ पर पहुंच सकता है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियम पर फिलहाल रोक लगाए जाने के बाद मशहूर कवि और राम कथावाचक कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया आई है। याद रहे दो दिन पहले कुमार विश्‍वास ने एक कविता सोशल मीडिया पर शेयर यूजीसी के नए नियम पर विरोध जताया था। जानिए कुमार विश्वास ने सुप्रीम के फैसले के बाद क्या ऐसा कहा जिसकी चर्चा हो रही है?

कुमार विश्वास ने मोदी सरकार

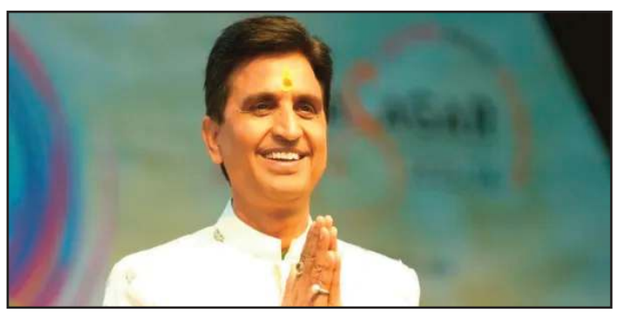

को किया अगाह

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुमार विश्वास ने यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भारत इस समय किसी भी प्रकार का विभाजन झेलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सरकारों और राजनीति को विभाजक रेखाएँ खींचने से बचना चाहिए। विश्वास ने स्वीकार किया कि दलित, पिछड़े और वंचित मित्रों के साथ सदियों से बहुत अत्याचार हुआ है।

'सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों लोगों की मनोदशा का भाव समझा'

विश्वास ने अपने बयान में आगे कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों लोगों की मनोदशा का भाव समझा।' उन्होंने यह भी जोड़ा कि 'यह भी कहने में लोगों की जबान हकलाती है कि ये सब जो पिछले एक हजार वर्षों में विधर्म भारत में आया था, जिनके यहां परंपराएं थीं, उन्होंने ये भारत में बोया था।'

कुमार विश्‍वास बोले- 'विधर्म' से मुक्ति के उपाय किए जा रहे हैं...

कुमार विश्‍वास के अनुसार इस 'विधर्म' से मुक्ति के उपाय किए जा रहे हैं, जो पिछले 80 वर्षों से जारी हैं और आगे भी होंगे। उन्होंने जोर दिया कि इस प्रक्रिया में कोई निरपराध व्यक्ति न फँसे, और न ही किसी जाति, वर्ण या धर्म का व्यक्ति असहज महसूस करे। विश्वास ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और उम्मीद जताई कि राजनीति भी इसका सकारात्मक हल निकालेगी।

कुमार विश्वास ने यूजीसी के नए नियम के विरोध में लिखी था- रौंया-रौंया उखाड़ लो राजा ..।

गौरतलब है कि दो दिन पहलेकवि कुमार विश्वास ने #UGC_RollBack हैशटैग के साथ यूजीसी नियमों पर अपना विरोध जताते हुए उन्होंने दिवंगत कवि रमेश रंजन की एक कविता साझा की, जिसकी पंक्तियाँ हैं: "चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, रोंया रोंया उखाड़ लो राजा.."!

कौलाछापर के ट्रॉफी पर एसएन मेमोरियल ने जमाया कब्जा

कौला छापर में आयोजित राज्य स्तरीय वॉलीबॉल ट्रॉफी के साथ विजेता टीम

देवरिया।देसही देवरिया के कौला छापर में आयोजित राज्य स्तरीय वालीबाल प्रतियोगिता का रंगारंग समापन बुधवार की रात हुआ। एसएन मेमोरियल ने प्रतियोगिता पर कब्जा जमा लिया। एसएन के खिलाड़ी मज को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया।

देर रात जुगनू स्पोर्ट क्लब कौलाछापर पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच एसएन मेमोरियल पब्लिक स्कूल और नौशाद वाराणसी के बीच खेला गया। एसएन ने पहला सेट 13-15 से जीता तो वहीं नौशाद वाराणसी की टीम के प्लेयर विकास ने खेल के अच्छे प्रदर्शन करते हुए दूसरा सेट 15-14 से अपने नाम कर लिया। एसएन के बेस्ट प्लेयर मज ने अपने दम पर दोनों सेट लगातार

16-15 और 15 -14 से जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। यूपी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट धर्मेश कुमार शाही डिप्टी एसपी एसटीएफ लखनऊ मुख्यालय खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और खेल प्रति जागरूक किए।

मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि देसही देवरिया इंजीनियर संजय तिवारी विशिष्ट भाजपा नेता सुनील राव के प्रतिनिधि गौरव मारी त्रिपाठी ने विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी वितरित किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष आफताब आलम ने अतिथियों को अंग वस्त्र व माला पहनकर फील्ड में स्वागत किया। रेफरी ब्यास चतुर्वेदी और अमित बच्चन रहे। सचिव ग्राम प्रधान मोहम्मद रफी खान ने सभी खिलाड़ियों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया। इस दौरान, अब्दुल रहमान, बेलाल अहमद, मोहम्मद रिजवान खान, हसनैन खान, सदरूद्दीन, गुलाम हैदर, साद, प्रबंधक रियाज खान, इन्फोटेक के डायरेक्टर रफीउल्लाह, खान, बसीर, सैफ, ग्राम प्रधान मोहम्मद फखरुद्दीन खान, हैदर वारिस, डॉक्टर सीटू, मैनुद्दीन खान उर्फ सोनू, मिराज खान, शाहिद खान, आदि उपस्थित रहे।

सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत कोकिंग कोयले को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया

(जीएनएस)।

खनन क्षेत्र में जारी संरचनात्मक सुधारों के अंतर्गत और आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) के अंतर्गत कोकिंग कोल को एक महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया है।

यह निर्णय विकसित भारत लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी-वीबी) की सिफारिशों और नीति आयोग से प्राप्त नीतिगत सुझावों के आधार पर लिया गया है, जिसमें खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने और घरेलू इस्पात क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में कोकिंग कोयले की रणनीतिक भूमिका को मान्यता दी गई है।

भारत में अनुमानित 37.37 अरब टन कोकिंग कोयले का भंडार है, जो मुख्य रूप से झारखंड में स्थित है, इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी भंडार मौजूद हैं। घरेलू स्तर पर इतनी उपलब्धता के बावजूद, कोकिंग कोयले का आयात 2020-21 में 51.20 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 57.58 मिलियन टन हो गया है। वर्तमान में, इस्पात क्षेत्र की कोकिंग कोयले की लगभग 95 प्रतिशत आवश्यकता आयात से पूरी होती है, जिससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का व्यय होता है।

इस निरंतर निर्भरता को दूर करने के लिए, केंद्र सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 11सी के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया है। तदनुसार, भाग अ में "कोयला" शब्द को अब "कोकिंग कोयला सहित कोयला" के रूप में पढ़ा जाएगा, और "कोकिंग कोयला" को भाग घ में शामिल किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की सूची है।

इस श्रेणी में कोकिंग कोयले को शामिल करने से अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी आने, व्यापार करने में सुगमता बढ़ने और गहरे भंडारों सहित अन्वेषण एवं खनन गतिविधियों में गति आने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण खनिजों के खनन को सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता से मुक्त रखा गया है और इससे क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए खराब हो चुकी वन भूमि के उपयोग की अनुमति मिलती है। इन उपायों से निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

इस सुधार से आयात पर निर्भरता कम होने, इस्पात क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बढ़ने और राष्ट्रीय इस्पात नीति के उद्देश्यों को समर्थन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, इससे अन्वेषण, शोधन और उन्नत खनन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में निजी निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ खनन, रसद और इस्पात मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन होने की भी उम्मीद है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 11डी (3) के अनुसार, रॉयल्टी, नीलामी प्रीमियम और खनन पट्टों से संबंधित अन्य वैधानिक भुगतान संबंधित राज्य सरकारों को प्राप्त होते रहेंगे, भले ही खनिज नीलामी केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाती हो।

महावन पुलिस ने चोरी की स्कूटी समेत लेखपाल को पकड़ा : दो वाहन चोर हुए फरार

मथुरा (जीएनएस)। थाना महावन क्षेत्र स्थित यमुना एक्सप्रेस-वे के जगदीशपुर पुल के पास से पुलिस ने चोरी की स्कूटी समेत शातिर वाहन चोर लेखपाल को दबोच लिया। पकड़े गए शातिर के दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी महावन चेतराम शर्मा और एसएसआई ध्यानवीर सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि यमुना एक्सप्रेस-वे के जगदीशपुल की ओर एमएस चाहर हॉस्पीटल के पास वाहन चोर खड़े हुए हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी चेतराम शर्मा और एसएसआई ध्यानवीर सिंह पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे शातिर वाहन चोर लेखपाल पुत्र सुनहरी लाल निवासी काजीपाड़ा कस्बा महावन को घेराबंदी करके दबोच लिया। जबकि पकड़े गए शातिर के साथी खिल्लो पुत्र साबू निवासी नई आबादी कस्बा महावन और आसू उर्फ शकील पुत्र वीरु निवासी व्यापारी मोहल्ला कस्बा महावन अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। पुलिस ने पकड़े गए शातिर के कब्जे से चोरी की एक स्कूटी बरामद

की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज दिया है।

सरेराह झगड़ा और पथराव करने वाले पांच शातिरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

: दो पक्षों में पथराव के बाद दहशत में आए लोगों ने छिपकर बचायी जान

मथुरा (जीएनएस)। थाना जमुनापार क्षेत्र स्थित राया रोड़ पर पथराव कर उपद्रव करने वाले 5 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार राया रोड़ स्थित भाष्कर हॉस्पीटल के सामने दो गुटों में झगड़े के बाद मारपीट और पथराव करके लोगों में दहशत फैला दी थी। किसी राहगीर ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। उपद्रव की सूचना मिलते थाना प्रभारी जमुनापार विदेश कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस को देखकर पथराव और उपद्रव कर रहे शातिर भागने लगे। पुलिस टीम ने घेराबंदी करके उपद्रव और पथराव करने वाले

शाहरूख पुत्र रहीम निवासी सिद्धार्थनगर थाना जमुनापार, अंसार पुत्र सुल्तान खां निवासी तेहरा थाना सुरीर, हाल निवासी कृष्णा विहार कॉलोनी राया रोड़ थाना जमुनापार, अख्तर अली पुत्र कल्लू अली निवासी सिद्धार्थ नगर थाना जमुनापार, मुन्ना पुत्र समीना निवासी बेसवां थाना गोरई जिला अलीगढ़, हाल निवासी अम्बेडकर नगर राया रोड़ थाना जमुनापार और नवीन पुत्र निजामुद्दीन निवासी बेसवां थाना गोरई जिला अलीगढ़, हाल निवासी अम्बेडकर नगर राया रोड़ थाना जमुनापार को घेरकर गिरफ्तार कर लिया। बताते चलें कि राया रोड़ पर भास्कर हॉस्पीटल के सामने दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। दोनों पक्षों ने सरेआम आकर एक दूसरे पर ईंट-पत्थर फेंके तो वहां अफरा-तफरी मच गई। उपद्रव को देखकर दुकानदार दहशत में आ गए थे और दुकानों के शटर गिराकर बंद हो गए थे। जमुनापार पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज दिया है।

फरवरी माह में होगा शुक्र ग्रह उदित, होंगे मांगलिक कार्य प्रारंभ

मथुरा ब्यूरो। (मुकेश कुशवाह) श्री दीपक ज्योतिष भागवत संस्थान की मंथन गोष्ठी रतनकुंड स्थित कैंप कार्यालय पर संस्थान के निदेशक ज्योतिषाचार्य पंडित कामेश्वरनाथ चतुर्वेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उन्होंने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 में शुक्र ग्रह अस्त हो गया था, जिसके कारण मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध लग गया था। बताया कि 1 फरवरी 2026 माघी पूर्णिमा को शुक्र ग्रह उदित होगा और सभी प्रकार के मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। इस मौके पर गोष्ठी में उपस्थित आचार्य ब्रजेन्द्र नागर और ज्योतिषाचार्य पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि परिवार में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मुहूर्तों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहा कि शुक्र ग्रह अस्त रहने पर किए गए मांगलिक कार्य सफल नहीं होते हैं। वहीं ज्योतिषाचार्य दीपक चतुर्वेदी एवं शरद साहित्याचर्य ने कहा कि 4 से 21 फरवरी तक सभी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं और 5 से 12 मार्च तक शुभमुहूर्त हैं।

आगे के मुहूर्त विक्रम संवत 2083 के पंचांग अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च से प्रारंभ होंगे। गोष्ठी में नारायण प्रसाद शर्मा, सौरभ शास्त्री, ऋषभ देव, गोविंद देव, मनोज पाठक मनीष पाठक, निरंजन शास्त्री आदि ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए जन सामान्य को जानकारी देने के उद्देश्य से बत कि फरवरी माह, वर्ष 2026 में 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 20 और 21 तारीख विवाह के लिए शुभमुहूर्त हैं, तथा मार्च माह में 5, 6, 9,10, 11 और 12 में शुभमुहूर्त रहेंगे। इस मौके पर गोष्ठी का संचालन सौरभ शास्त्री ने किया।

केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करने में दूरसंचार विभाग की उपलब्धियों और आने वाले वर्षों के लिए विजन प्रस्तुत किया

भारतनेट योजना के तहत हर घर तक फाइबर कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य, 1.5 करोड़ एफटीटीएच कनेक्शन के साथ, पहले ही लगभग 7 लाख किमी ओएफसी बिछाया जा चुका

भारतनेट उद्यमियों (बीएनयू) को पूंजीगत एवं परिचालन सब्सिडी तथा ग्रामीण कनेक्टिविटी को रोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ने के लिए गुजरात ने 100% लक्ष्य हासिल किया

गुजरात सरकार एवं जीएफजीएनएल के बीच डिजिटल भारत निधि एवं बीएसएनएल के साथ चतुर्भुज समझौते के माध्यम से आगे विस्तार की तैयारी

(जीएनएस)।

केंद्रीय संचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राज्यसभा को सूचित किया कि ग्राम पंचायतों (जीपी) को कनेक्टिविटी प्रदान करने में दूरसंचार विभाग की प्रगति उल्लेखनीय रही है। उन्होंने भविष्य की रूपरेखा के बारे में रेखांकित करते हुए कहा कि भारतनेट

अब केवल एक कनेक्टिविटी परियोजना नहीं रह गया है, बल्कि यह ग्रामीण एवं शहरी भारत दोनों को भारत के डिजिटल परिवर्तन की रीढ़ बन चुका है।

सदन में एक प्रश्न के उत्तर में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का विजन प्रत्येक नागरिक को विश्वस्तरीय, तीव्र एवं विश्वसनीय ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन, व्यवसाय एवं रोजगार में परिवर्तनकारी बदलाव सशक्त बनाने वाला राष्ट्रीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है।

भारतनेट-1 एवं 2 के तहत 97% ग्राम पंचायत कनेक्टिविटी हासिल

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतनेट-1 एवं भारतनेट-2 के तहत देश भर में 2.22 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब तक लगभग 2.15 लाख ग्राम पंचायतें—अर्थात लगभग 97%—को जोड़ा जा चुका है, जिसमें देशभर में करीब 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। इससे ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन एवं स्थानीय उद्यमिता को काफी मजबूती मिली है।

संशोधित भारतनेटः दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड विस्तार

श्री सिंधिया ने रेखांकित किया कि सरकार ने 2023 के अंत और 2024 में संशोधित भारतनेट योजना को मंजूरी दी, जो दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीगत व्यय ब्रॉडबैंड कार्यक्रम है, जिसमें कुल ₹1.40 लाख करोड़ (लगभग 16 अरब अमेरिकी डॉलर) का प्रावधान है। यह योजना ग्राम पंचायतों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लगभग 6.5 लाख गांवों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करेगी।

नागर विमानन बुनियादी ढांचे की विकास परियोजना का उद्घाटन

(जीएनएस)।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता ने पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर एयर मार्शल जेएस मान की उपस्थिति में 28 जनवरी 2026 को एयर फोर्स स्टेशन लेह में नागर विमानन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से एक परियोजना का उद्घाटन किया।

यह उद्घाटन लद्दाख में नागर विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सिविल प्रशासन एवं क्षेत्र के विकास में शामिल सभी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग की भावना को परिपुष्ट बनाने में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बेहद चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाले क्षेत्र

और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड समय में उन्नयन किया गया है।

विकसित किया गया बुनियादी ढांचा विमानों की जमीनी आवाजाही को आसान बनाने के साथ-साथ नागरिक उड़ानों के प्रस्थान को तेज करेगा। इन सुधारों से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और समय की बचत होगी।

बेहतर वायु संपर्क लेह क्षेत्र में पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा देने के साथ-साथ आर्थिक अवसरों का सृजन करेगा और स्थानीय आजीविका का समर्थन करेगा। साथ ही, बेहतर सुविधाएं निवासियों और आगंतुकों दोनों के लिए अधिक विश्वसनीय हवाई सेवाएं सुनिश्चित करेंगी, जबकि मानवीय सहायता और आपदा राहत आवश्यकताओं पर तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षेत्र की क्षमता को भी मजबूती मिलेगी।

यह विकास लद्दाख के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास में सार्थक योगदान देगा।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 31 जनवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर

महानदी भवन, नया रायपुर में मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में कृषि व ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे श्री शिवराज सिंह

31 जनवरी को छत्तीसगढ़ के किसानों से सीधा संवाद करेंगे केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

गिरहोलाझखपरी में खेत भ्रमण, कुम्हारी में किसान मेले में होंगे शामिल

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 31 जनवरी 2026 को एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ जाएंगे। राजधानी रायपुर, दुर्ग एवं नया रायपुर में होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से वे किसानों से सीधा संवाद करेंगे, वहीं मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 31 जनवरी को रायपुर पहुंचेंगे।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान रायपुर से गिरहोला, खपरी (जिला दुर्ग) के लिए प्रस्थान करेंगे और वे ग्राम गिरहोला एवं ग्राम खपरी में खेत भ्रमण और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेकर किसानों से सीधा संवाद करेंगे। यहां वे केंद्र की प्रमुख कृषि योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्राकृतिक खेती एवं सूक्ष्म सिंचाई (ढटडर) आदि के लाभों पर भी चर्चा करेंगे, ताकि अधिक से अधिक किसान इन योजनाओं से जुड़ सकें।

दोपहर के बाद श्री चौहान गांव खपरी से निकलकर दुर्ग जिले के कुम्हारी पहुंचेंगे, जहां वे छत्तीसगढ़ यूथ प्रोग्रेसिव फार्मर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित किसान मेले में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वे आधुनिक कृषि तकनीकों, फसल विविधीकरण, किसान उत्पादक संगठनों (ऋछड), डिजिटल एग्रीकल्चर और ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के रोडमैप पर अपने विचार रखेंगे।

किसान मेले और किसान संवाद के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार की कई प्रमुख योजनाओं पर विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को सीधे लाभांतरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए प्राकृतिक आपदाओं से फसल सुरक्षा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, डिजिटल कृषि मिशन और ड्रोन तकनीक के उपयोग पर बल देने के साथ ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए गांवों की बुनियादी ढांचा एवं आजीविका सुदृढ़ीकरण पर विशेष चर्चा करेंगे। इन योजनाओं के प्रभाव से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में किसानों- ग्रामीणों की आय बढ़ाने, उनकी समृद्धि तथा गांवों को सड़कों, आवास और स्व-सहायता समूहों के माध्यम से मजबूत बनाने का संदेश वे विस्तार से रखेंगे।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान नया रायपुर स्थित महानदी भवन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और राज्य के कृषि मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं की प्रगति का आकलन करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास स्वीकृति एवं निर्माण की स्थिति, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण, साथ ही प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना, जैविक एवं प्राकृतिक खेती के विस्तार, बीज एवं खाद की उपलब्धता, क्रेडिट सुविधा, एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड आदि विषयों की समीक्षा की जाएगी।

इस दौरे के माध्यम से केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के किसानों, ग्रामीण समाज और राज्य सरकार के साथ मिलकर कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए नए संकल्पों और ठोस कार्ययोजना को आगे बढ़ाने का संदेश देने वाले हैं, साथ ही यह उनका देशभर में राज्यवार और क्षेत्रवार कृषि एवं ग्रामीण विकास की रणनीति का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में उद्योग के सकल मूल्य संवर्धन में वास्तविक आधार पर साल दर साल 7.0 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ भारत का औद्योगिक प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है: आर्थिक समीक्षा 2025-26

भारत के कुल विनिर्माण मूल्य संवर्धन में मध्यम और उच्च-प्रौद्योगिकी गतिविधियों का योगदान 46.3 प्रतिशत रहा

समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 25 के दौरान गैर बैंक स्रोतों से वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए वित्त के प्रवाह में 17.32 प्रतिशत सीएजीआर बढ़ोतरी दर्ज की गई

भारत के इस्पात और सीमेंट के दूसरे सबसे बड़े वैश्विक उत्पादक बने रहने के साथ, मुख्य उद्योगों की मजबूत बढ़ोतरी बरकरार रही

1,047.52 मिलियन टन (एमटी) कोयले के उत्पादन के साथ, भारत का कोयला उद्योग वित्त वर्ष 25 में ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया

वित्त वर्ष 15-25 के दौरान वाहन उद्योग ने उत्पादन में लगभग 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कई पहल कीं

इलेक्ट्रॉनिक्स के सातवीं से तीसरी सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी (वित्त वर्ष 22-25) बनने के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण उद्योग वृद्धि को समर्थन देने वाले प्रमुख क्षेत्र के तौर पर उभरा

(जीएनएस)।

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2025-26 पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में वास्तविक आधार पर उद्योग का संवर्धित सकल मूल्य (जीवीए) में साल दर साल 7.0 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ भारत का औद्योगिक प्रदर्शन मजबूत बना रहा। इससे पिछले वित्त वर्ष (2024-25) में वृद्धि में 5.9 प्रतिशत की नरमी के बाद यह अच्छी बढ़ोतरी का संकेत है।

आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, वित्त वर्ष 26 की पहली और दूसरी तिमाही में विनिर्माण जीवीए क्रमशः 7.72 और 9.13 प्रतिशत बढ़ा। इस सुधार की मुख्य वजह विनिर्माण क्षेत्र में जारी ढांचागत बदलाव हैं, जिनमें धीरे-धीरे मंहगे विनिर्माण खंड की ओर रुझान, कॉरिडोर आधारित विकास के माध्यम से औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता में सुधार और प्रौद्योगिकी को बड़े स्तर पर अपनाना एवं कंपनियों का औपचारीकरण शामिल हैं।

आर्थिक समीक्षा कहती है कि भारत के कुल विनिर्माण मूल्य संवर्धन में मध्यम और उच्च प्रौद्योगिकी गतिविधियों की हिस्सेदारी 46.3 प्रतिशत हो गई। इसकी मुख्य वजह उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं और भारतीय सेमीकंडटर मिशन जैसी विभिन्न सरकारी पहल के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्युटिकल, रसायन और परिवहन क्षेत्रों में घरेलू क्षमता में विस्तार हैं। समीक्षा में 2023 में प्रतिस्पर्धी औद्योगिक प्रदर्शन (सीआईपी) के मामले में भारत की रैंकिंग सुधरकर 37वें पायदान पर पहुंचने के साथ देश की वैश्विक स्थिति में मजबूती की बात कही गई, जबकि 2022 में भारत 40वें पायदान पर था।

समीक्षा कहती है कि भले ही, वाणिज्यिक बैंकों की तरफ से बैंक आधारित औद्योगिक कर्ज में बढ़ोतरी वित्त वर्ष 24 के 9.39 प्रतिशत की तुलना में घटकर वित्त वर्ष 25 में 8.24 प्रतिशत रह गई, लेकिन विभिन्न आकलनों से वर्तमान में जारी विविधीकरण के चलते बैंकों से वित्त के स्रोतों के दूर होने के संकेत मिले हैं। अगस्त 2025 की मासिक आर्थिक समीक्षा का उल्लेख करते हुए समीक्षा कहती है, 'बैंक कर्ज में कमी वाणिज्यिक क्षेत्र के वित्तीय संसाधनों के समग्र प्रवाह में बढोतरी से मेल खाती है। वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 25 के दौरान गैर बैंक स्रोतों से वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए वित्त के प्रवाह में 17.32 की सीएजीआर बढोतरी दर्ज की गई।

मुख्य इनपुट उद्योग

आर्थिक समीक्षा जोर देकर कहती है कि भारत के इस्पात और सीमेंट क्षेत्र में दुनिया के दूसरे बड़े उत्पादक बने रहने के साथ मुख्य उद्योगों का प्रदर्शन मजबूत रहा है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा बड़ा सीमेट उत्पादक है। प्रति व्यक्ति 540 किलोग्राम के वैश्विक औसत की तुलना में भारत में सीमेंट की घरेलू खपत प्रति व्यक्ति लगभग 290 किलोग्राम है। समीक्षा कहती है कि सरकार का मुख्य रूप से राजमार्ग, रेलवे, आवासीय योजनाओं, स्मार्ट सिटीज जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और ग्रामीण विकास एवं औद्योगिक वृद्धि पर जोर है, जिससे सीमेंट की मांग में खासी बढ़ोतरी का अनुमान है।

निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र से मजबूत घरेलू मांग के चलते, बीते पांच साल में इस्पात क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिला।

वित्त वर्ष 25 में 1,047.52 मिलियन टन (एमटी) कोयला उत्पादन के साथ भारत का कोयला उद्योग ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया। यह उत्पादन बीते वित्त वर्ष के 997.83 एमटी की तुलना में 4.98 प्रतिशत ज्यादा था।

रसायन और पेट्रो-रसायन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका बनी रही, जिसने वित्त वर्ष 24 में समग्र विनिर्माण क्षेत्र के जीवीए में 8.1 प्रतिशत का योगदान किया।

वित्त वर्ष 15-25 के दौरान वाहन उद्योग के उत्पादन में लगभग 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क के तहत बृहन्मुंबई नगर निगम को 17 लाख रुपये वितरित किए

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और उनसे प्राप्त लाभों के निष्पक्ष और समान वितरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ा रहा है। एनबीए ने एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (एबीएस) फ्रेमवर्क के तहत महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) को 17 लाख रुपये वितरित किए हैं।

यह धनराशि बैसिलस जीनस से संबंधित मृदा सूक्ष्मजीवों के व्यावसायिक उपयोग से प्राप्त हुई है। इन सूक्ष्मजीवों का उपयोग मूल्यवर्धित प्रोबायोटिक उत्पादों के विकास में किया गया है, जो जैव विविधता संरक्षण और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के बीच प्रभावी संबंध को दशार्ता है। लाभ-साझाकरण व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि जैविक संसाधनों से प्राप्त व्यावसायिक लाभों का एक हिस्सा स्थानीय समुदायों को वापस दिया जाए, जिससे सामुदायिक स्तर पर विकास पहलों को समर्थन मिले।

जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बढ़ते रुझान से सूक्ष्मजीव औद्योगिक नवाचार के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में उभर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने एबीएस निधि में लगभग 10 करोड़ रुपये का योगदान दिया है, जो स्वास्थ्य सेवा, कृषि और औद्योगिक अनुप्रयोगों जैसे क्षेत्रों में सूक्ष्मजीव संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका को दशार्ता है।

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के बाद, जैव विविधता अनुदान (एबीएस) से लाभान्वित होने वाला दूसरा प्रमुख राज्य बना हुआ है। लाल चंदन की लकड़ी से प्राप्त लाभ-साझाकरण राशि को छोड़कर, महाराष्ट्र को एबीएस वितरण का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ है। वर्तमान आवंटन के साथ, महाराष्ट्र को दी गई कुल एबीएस सहायता लगभग 8 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जिससे राज्य भर में 200 से अधिक जैव विविधता प्रबंधन समितियों और सात संस्थानों को लाभ मिला है।

राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता निधि (एबीएस) के तहत कुल वितरण 144.37 करोड़ रुपये (लगभग 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का आंकड़ा पार कर चुका है। यह उपलब्धि जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रभावी कार्यान्वयन को दशार्ती है और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचे के तहत देश की प्रतिबद्धताओं, विशेष रूप से लक्ष्य 13 और 19 को आगे बढ़ाती है। ये परिणाम देश के राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य 13 और 19 के अनुरूप भी हैं, जो जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और स्थानीय समुदायों के साथ समान लाभ साझाकरण, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के सशक्तिकरण और आजीविका सुरक्षा में वृद्धि पर जोर देते हैं।

एबीएस ढांचा सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देता है। ये सभी परिणाम जैव विविधता पर आयोजित सम्मेलन और इसके नागोया प्रोटोकॉल के वैश्विक कार्यान्वयन में भारत के नेतृत्व को सुदृढ़ करते हैं, साथ ही जैव विविधता संरक्षण और समावेशी विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं।